Scholarly Research Journal for Humanity Science & English Language,
Online ISSN 2348-3083, SJIF 2016 = 4.44, www.srjis.com
UGC Approved Sr. No.48612, AUG-SEPT 2017, VOL- 4/23
https://doi.org/10.21922/srjhsel.v4i23.9644

vkfFkd lof) vkj jkstxkj dk lUnHk e fu;ktu dh Hkfedk dk fo'लेशणात्मक अध्ययन–

vuli dekj flg[1], **Ph. D.** & food fo'odek[2]

[1]सहायक प्राध्यापक (असि0प्रो0), व्यावहारिक अर्थशास्त्र विभाग, वाणिज्य संकाय, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।

[2]शोधार्थी, व्यावहारिक अर्थशास्त्र विभाग, वाणिज्य संकाय, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।

Scholarly Research Journal's is licensed Based on a work at www.srjis.com

प्रत्येक काल खण्ड में, अर्थशास्त्र अथवा राष्ट्र की मूलभूत चुनौती अपनी जनसंख्या की आवश्यकता की प्रत्येक वस्तुएँ और सेवाएँ समुचित परिमाण में उपलब्ध कराकर उनके जीवन स्तर में उत्तरोत्तर वृद्धि करना है। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु प्रत्येक देश को धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक स्थितियों के आधार पर महत्त्वपूर्ण आर्थिक निर्णय लेने होते हैं। इन्हीं आर्थिक निर्णयों से एक आर्थिक स्वरूप का निर्माण होता है, जिसे ^vFk0;oLFkk dk lxBu* या ^vFk0;oLFkk* के नाम से जाना जाता है। वैश्विक स्तर पर आर्थिक संवृद्धि एवं विकास हेतु पूँजीवादी, समाजवादी और मिश्रित आर्थिक प्रणालियों को अर्थव्यवस्था स्वरूप अपनाया गया। देश के नागरिकों के जीवन स्तर में उत्तरोत्तर वृद्धि एवं सुधार के उद्देश्य को दृष्टिगत रखते हुए भारत ने, प्रथम औद्योगिक नीति प्रस्ताव–1948, आर्थिक नियोजन अपनाते हुए मिश्रित आर्थिक प्रणाली को अपनाया और पंचवर्षीय योजना के आधार पर संवृद्धि, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता और समानता के लक्ष्यों की प्राप्ति को सुनिश्चित किया था। नियोजकों ने उपरोक्त लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु सकल घरेलू उत्पाद में तीव्र वृद्धि प्राप्ति को एक महत्त्वपूर्ण कारक माना। नियोजनकर्त्ताओं का मानना है कि उच्चतम जी0डी0पी0 संवृद्धि दर की प्राप्ति से नए रोज़गारों का सृजन कर बेरोज़गारी, निर्धनता, आर्थिक असमानता जैसी सामाजिक–आर्थिक समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। वस्तुतः नियोजन अवधि में प्राप्त परिणामों से स्पष्ट होता है कि संवृद्धि दर और रोज़गार स्तर में न तो कोई सीधा सम्बन्ध है, न ही नियोजन प्रक्रिया ने रोज़गार स्तर को बढ़ाने में कोई सार्थक भूमिका निभायी।

Copyright © 2017, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

भारत में वर्ष 1970 से पूर्व बेरोज़गारी को गम्भीर सामाजिक समस्या न मानने के कारण रोज़गार और बेरोज़गारी सम्बन्धी समंकों का आकलन हेतु कोई व्यापक एवं संगठित सरकारी सर्वेक्षण नहीं किया गया। रोज़गार और बेरोज़गारी सम्बन्धी व्यापक आंकड़ों की उपलब्धता वर्ष 1972–73 से प्राप्त होती है। वर्ष 1972–73 एन0एस0एस0ओ0 का 27वाँ दौर का वर्ष था, जो मुख्यतः रोज़गार ओर बेरोजगारी के प्रथम सर्वेक्षण से सम्बन्धित था। इस सन्दर्भ हेतु अब तक नौ पंच वार्षिक सर्वेक्षण किए गए हैं। इसका 68वाँ दौर (जुलाई 2011 से जून 2012) रोज़गार और बेरोज़गारी से सम्बन्धित 9वाँ सर्वेक्षण है।

lkj.kh 1 jkstxkj] jkstxkj ykp vkj ldy ?kjy mRikn lof) nj

¼lh0,0th0vkj0 vfHkxe vk/kkfjr½

,u0,l0,l0vk0 nkj ¼lo{k.k vof/k½	jkstxkj lof) nj[1]	th0Mh0ih0 lof) nj	jkstxkj ykp
1972–73 से 1977–78	2.6	4.6	0.57
1977–78 से 1983	2.1	3.9	0.54
1983 से 1987–88	1.7	4.2	0.42
1987–88 से 1993–94	2.4	5.6	0.43
1993–94 से 1999–2000	1.0	6.8	0.15
1999–2000 से 2004–05	2.8	5.7	0.50
2004–05 से 2009–10	0.1	8.7	0.01
2009–10 से 2011–12	1.4	7.8	0.18

स्रोत– 1. आर्थिक समीक्षा 2015–16 की सारणी 1.3(क) और (ख), 1.4(क) और (ख), 1. 5(क), 1.8 और 1.9 पृष्ठ सं0 23 से 29 और 23 से 38।

2. एस 01 नेशनल एकॉउन्ट्स स्टेटिस्टिक्स 2012 और एस 01 नेशनल एकॉउन्ट्स स्टेटिस्टिक्स 2014, केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय।

3. सारणी संख्या 4, मिश्रा, संगीता एण्ड सुरेश ''एस्टिमेटिंग एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी ऑफ ग्रोथ फार दी इंण्डियन इकोनमी, जून 2014।

टिप्पणी[1]– रोज़गार संवृद्धि दर राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय द्वारा रोज़गार एवम् बेरोज़गारी संबंधी किये गये अब तक विभिन्न नौ पंच वार्षिक सर्वेक्षणों के आँकाड़ों पर आधारित है।

Copyright © 2017, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

आरेख संख्या 01

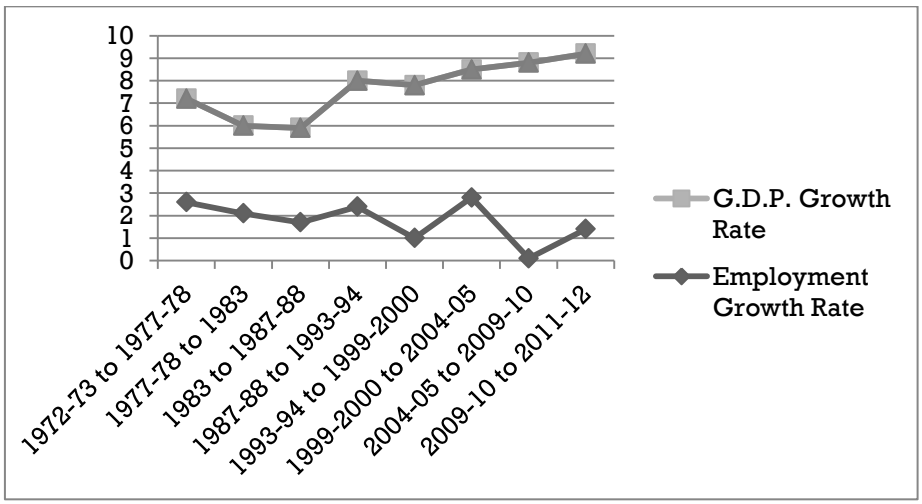

lkf[;dh; mi&ifjdYiuk ijh{kk

रोज़गार और जी0डी0पी0 संवृद्धि दर के मध्य सम्बन्ध को, उप–परिकल्पना की सार्थकता का परीक्षण कर, सहसम्बन्ध–सांख्यिकीय–परीक्षा के आधार पर स्पष्ट किया गया–

H_0 : (निराकरणीय उप–परिकल्पना) रोज़गार और सकल घरेलू उत्पाद संवृद्धि दरों के मध्य कोई सार्थक सम्बन्ध न होना।

H_1 : (वैकल्पिक उप–परिकल्पना) रोज़गार और सकल घरेलू उत्पाद संवृद्धि दरों के मध्य एक सार्थक सम्बन्ध होना।

mi&ifjdYiuk ijh{kk

lglEcU/k	lglEcU/k	jkstxkj lof)	th0Mh0ih0 lof)
रोज़गार संवृद्धि	कार्ल पियरसन सहसम्बन्ध	1	–0.721
	सार्थकता (द्वि–पुच्छ) Sig.(2-tailed)		0.043
	प्रतिदर्श संख्या (N)	8	1
जी0डी0पी0 संवृद्धि	कार्ल पियरसन सहसम्बन्ध	–0.721	1
	सार्थकता (द्वि–पुच्छ) Sig.(2-tailed)	0.043	
	प्रतिदर्श संख्या (N)	8	8

निष्कर्ष– परिकलित द्वि–पुच्छ का मान 0.043 है जो सार्थकता स्तर 0.05 के मान से कम है। अतः निराकरणीय उप–परिकल्पना (H_0) अस्वीकार्य योग्य है। स्पष्ट है कि रोज़गार और

जी0डी0पी0 संवृद्धि दर के मध्य दृष्टिगत सार्थक ऋणात्मक सहसम्बन्ध के फलस्वरूप वैकल्पिक उप–परिकल्पना (H_1) स्वीकार्य योग्य है।

आरेख और सहसम्बन्ध–सांख्यिकीय–परीक्षा से परिकलित निष्कर्ष से ज्ञात होता है कि रोज़गार संवृद्धि और जी0डी0पी0 संवृद्धि दर में बढ़ता हुआ अन्तराल रोज़गारहीन संवृद्धि का सूचक है। इससे स्पष्ट है कि बढ़ती हुई आर्थिक संवृद्धि के साथ–साथ रोज़गार स्तर में कमी होती रही है। इस सन्दर्भ में xka/kh th का मानना था कि ^^ykHk dh Hkkouk ls izsfjr vR;f/kd c<rk gqvk mRiknu yk[kksa ykxksa ds thou Lrj dks Åapk mBk ugha ldrk] tSls fd iwathoknh iz.kkyh ds vUrxZr futh mn~;e vf/kdre ykHk dh Hkkouk ls mRiknu djrs gSa] u fd ykxksa ds thou Lrj dks Åapk mBkus ds mn~ns'; dks /;ku esa j[krs gq, mRiknu ifjek.k dks c<+kus ds fy, mRiknu djrs gSaA**

विकास अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य आर्थिक ठहराव को समाप्त करना एवम् आर्थिक संवृद्धि की गति में तीव्रता लाना है। इन उद्देश्यों की प्राप्ति में पूँजीवादी आर्थिक प्रणाली अपवर्जक का कार्य करती है।

प्रो0 बरॉन ने यह अनुभव किया है कि ‘‘सामाजिक घटना के रूप में अपरिमेयता (असंगति व तर्कहीनता) पर तब तक नियंत्रण नहीं किया अथवा पाया जा सकता है, जब तक इसका आधार पूँजीवादी व्यवस्था में उत्पादक–मशीनें बड़े ही अनिश्चित और असंगत ढंग से कार्य करती हैं, जो अकल्पनीय है। सहयोग की कमी, व्यापार चक्र की संक्रिया में उच्चावचन, आर्थिक असमानता, सामाजिक परजीविता, आर्थिक असुरक्षा, अपशिष्ट प्रतिद्वन्द्विता, औद्योगिक अशान्ति इत्यादि समस्याएँ सामाजिक लगती है। जबकि पूँजीवाद की ये कुछ अवांछनीय अभिव्यक्तियाँ हैं। वैयक्तिक उद्यमों की प्रतिरोधी सामाजिक गतिविधियों के विषय में जितना कहा जाये उतना कम है। इसलिए विकासशील देशों में यदि तीव्र आर्थिक विकास को प्राप्त करना है, तो सार्वजनिक क्षेत्र ही उपयुक्त है।

उपरोक्त कारण पूँजीवाद और कीमत तंत्र अर्थात माँग और संपूर्ति पर आधारित कीमत निर्धारण प्रणाली की समाप्ति आर्थिक नियोजन को आवश्यक बनाती है। आर्थिक नियोजन को अपनाने सम्बन्धी विचारों में तार्किक अन्तर हो सकते हैं। यदि एक नई अर्थव्यवस्था आर्थिक नियोजन को अपनाती है, तो ऐसी अर्थव्यवस्था का भविष्य अज्ञात

Copyright © 2017, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

मात्रात्मक व परिमाणात्मक प्रारूप (मॉडल) पर आधारित होता है। इसके विपरीत विकासशील एवम् पिछड़ी अर्थव्यवस्थाओं की स्थिति अलग होती है। ये अर्थव्यवस्थाएँ नियोजन प्रणाली को शुरू कर चुकी अर्थव्यवस्थाओं के संवृद्धि पथ का केवल अनुसरण कर रही होती हैं। इन देशों में नियोजनकर्त्ताओं द्वारा गलती करने की सम्भावना कम होती है क्योंकि उनके पास नियोजित अर्थव्यस्थाओं के आर्थिक प्रारूप (मॉडल) मौजूद होते हैं, और जिन्हें वे लाभ के साथ अपना सकते हैं। तीव्र आर्थिक संवृद्धि के मुख्य लक्ष्य की प्राप्ति में एक नियोजित अर्थव्यवस्था अनियोजित अर्थव्यवस्था से हमेशा श्रेष्ठ होती है।

नियोजन समिति अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के लिए ठोस लक्ष्यों को निश्चित करके एक निश्चित समयावधि में उनकी प्राप्ति हेतु प्रभावी क्रियान्वयन करती है और नियोजन के अच्छे व बेहतर परिणाम एवम् उपलब्धियों की प्राप्ति हेतु समयावधि के साथ–साथ विभिन्न लक्ष्यों को प्रगतिशील आधार निर्धारित करती है। एक निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के पश्चात् ही उत्तरोत्तर प्राथमिकता के आधार पर निर्धारित लक्ष्यों को अपनाकर नियोजन के मुख्य उद्देश्य की प्राप्ति सम्भव है। अतः ऐसा तभी सम्भव है जब नियोजन पूर्ण नियोजित हो अर्थात् अर्थव्यवस्था के विकास हेतु बलातपूर्वक नियोजन का अंगीकरण न किया गया हो। भारतीय सन्दर्भ में भी स्वतंत्रता पश्चात् गतिहीन अर्थव्यवस्था को तीव्र संवृद्धि–गति प्रदान करने हेतु नियोजन को अपनाया गया। इससे संवृद्धि दर में वृद्धि तो हुई लेकिन विरूद्धता बेरोज़गारी में भी लगातार वृद्धि होती गई।

Hkkjr e: jkstxkj vkSj cjkstxkjh dh izo`fRr

lkj.kh l[;k 02 ¼;w0ih0,l0,l0½

ladsrd	वर्ष 1973	1983	1994	2005	2012
रोज़गार (मिलियन में)	236.3	299.5	376.9	461.1	474.8
बेरोज़गार (मिलियन में)	3.9	5.8	7.4	11	11.1
बेरोज़गार दर (प्रतिशत में)	1.6	1.9	1.9	2.3	2.2
रोज़गार लोच (प्रतिशत में)	–	0.52	0.47	0.30	0.05

स्रोत– 1. एन0एस0एस0ओ0 रिपोर्ट संख्या 484।

2. एन0एस0एस0ओ0 रिपोर्ट संख्या 554।

3. सारणी संख्या 02, अग्रवाल, आराधना (2014) : न्यू इनसाइट्स इनटू द रिलेशनशिप बिट्वीन एम्प्लॉयमेंट एण्ड इकनोमिक ग्रोथ इन इण्डिया।

उपरोक्त सारणी का विश्लेषण करने से प्राप्त रोज़गार एवं बेरोज़गारी सम्बन्धित निष्कर्षों के आधार पर नियोजन की भूमिका की यथार्थता ज्ञात होती है। इसका और अधिक आर्थिक विश्लेषण अधोलिखित रूप में कर सकते हैं–

1. भारत में बेरोज़गारी के आकलन की सामान्य अवस्थिति (UPSS) के आधार पर प्राप्त निष्कर्ष दर्शाते हैं कि लगातार खुली बेरोजगारी की दर में वृद्धि हुई। वर्ष 1973 में बेरोज़गारी दर 1.6 प्रतिशत थी जो वर्ष 2012 में बढ़कर 2.2 प्रतिशत हो गई। इसके अतिरिक्त रोज़गार–लोच में गिरावट आयी जो उपरोक्त वर्षों में क्रमशः 0.52 प्रतिशत से कम होकर 0.05 प्रतिशत हो गई। इसका आशय है कि आर्थिक संवृद्धि हेतु महत्त्वपूर्ण माना जाने वाला निर्धारक घटक सकल घरेलू उत्पाद द्वारा रोजगार स्तर में वृद्धि नहीं हुई जबकि रोज़गार लोच को प्रति इकाई उत्पादन वृद्धि की अनुक्रिया के फलस्वरूप रोज़गार में होने वाली वृद्धि के अनुपात के रूप में परिभाषित करते हैं।
2. भारत में श्रम बाज़ार, निम्न खुली बेरोज़गारी के साथ–साथ निम्न आय अथवा निम्न–मध्यम–आय बाज़ार का प्रतिरूप है। अधिकतम जनसंख्या निम्न आय से संबंधित होने के कारण अधिक समय तक बेरोज़गार नहीं रह सकती और उन्हें पेट की आग बुझाने के लिए किसी न किसी कार्य में संलग्न होना पड़ता है। इस कारण श्रम शक्ति का एक बड़ा भाग कृषि व अन्य स्वरोज़गार में कार्यशील हो जाता है, जो भारत में स्थायी व दीर्घकालीन प्रच्छन्न बेरोज़गारी के चक्रीय अवस्था को बनाये रखता है। कृषि व उससे संबंधित क्षेत्रों में 25 से 30 प्रतिशत लोग प्रच्छन्न बेरोज़गार हैं। कार्यबल स्वरोज़गार में 30 प्रतिशत से अधिक कार्यबल आकस्मिक मजदूरी और 16 प्रतिशत के लगभग नियमित वेतन व मजदूरी सम्बन्धित रोज़गार में संलग्न हैं। रोज़गार के उपरोक्त वर्गानुसार श्रमिकों के वितरण की स्थिति के अतिरिक्त कार्यशील जनसंख्या का व्यावसायिक ढाँचे के अनुसार वितरण और निर्धनता की स्थिति भी अत्यन्त चिन्ताजनक है। भारत में 60 प्रतिशत से अधिक कार्यशील जनसंख्या कृषि व उससे सम्बन्धित क्षेत्र में संलग्न होकर जी0डी0पी0 में केवल 14 से 15 प्रतिशत का योगदान देती है। निर्धनता की दृष्टिकोण से देखा जाये तो वर्ष 1973 में 320 मिलियन से अधिक व्यक्ति निर्धनता की रेखा से नीचे

Copyright © 2017, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

थे। वर्ष 2011–12 में यह संख्या कम होकर 270 मिलियन रह गई। लेकिन इस सन्दर्भ में दो महत्त्वपूर्ण तथ्य दृष्टिगत होते हैं– पहला, 44 वर्षों में केवल 50 मिलियन व्यक्ति निर्धनता रेखा से ऊपर आ सके और दूसरा, वर्ष 1973–74 में 80 प्रतिशत से अधिक निर्धन ग्रामीण क्षेत्रों में बसे थे, यह स्थिति 2011–12 में भी नहीं बदली।

3. रोज़गार के सम्बन्ध में नियोजन प्रक्रिया पूर्णतया नियोजित नहीं रही और इसका आंशिक सकारात्मक प्रभाव 1970 के दशक तक ही दृष्टिगोचर होता है। इस दशक में बेरोज़गारी की दर 1.6 प्रतिशत थी क्योंकि इस समय निर्धनता और आर्थिक असमानता को कम करने हेतु नीतियों का समावेशन नियोजन प्रक्रिया में किया गया था।

द्वितीय विश्व युद्ध के उपरान्त, जिन पूर्वी देशों दक्षिण कोरिया, हांगकांग, ताइवान, मलेशिया द्वारा मिश्रित आर्थिक प्रणाली अपनायी गयी थी। उन्होंने 1960 के दशक के मध्य में मिश्रित अर्थव्यवस्था को पूँजीवाद की तरफ ज्यादा झुकाया। परिणामस्वरूप इन अर्थव्यवस्थाओं द्वारा उच्च वृद्धि और विकास प्राप्त कर ली गयी। इनकी आर्थिक सफलता विश्व के लिए मिश्रित अर्थव्यवस्था का एक सफल प्रारूप उपलब्ध करा रहा था। इस वैश्विक आर्थिक घटना का प्रभाव भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी पड़ा। इसके कारण भारत में द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कृषि को प्राथमिकता न देते हुए औद्योगिक विकास को प्राथमिकता दी गई और 1980 का दशक आते–आते कल्याणकारी राज्य संवृद्धि मॉडल का स्थान बाजार आधारित योजनाएँ लेने लगी। अतः 1980 के दशक में बेरोज़गारी की दर 1.6 प्रतिशत से अधिक होकर 1.9 प्रतिशत हो गई।

4. बीसवीं सदी का आठवां दशक (1980s) विश्व की अर्थव्यवस्थाओं में आर्थिक सुधारों (Economic reforms) की शुरूआत का काल रहा। **वाशिंगटन समिति ने अमेरिकी** vFk0;oLFkk e: ljdkj dh Hkfedk dk ?kVku dh lykg nh Fkh। इस सहमति का प्रभाव भारत के आर्थिक नीतियों पर दिखायी देता है, (विशेषकर औद्योगिक नीति 1984 और 1985 पर) लेकिन इस दौर में इसे खुलकर नहीं अपनाया गया। योजना आयोग द्वारा ऐसी नीति परिवर्तन की सलाह 1985 में दी

जा चुकी थी। भारत द्वारा जिस आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया की शुरूआत 1991 में की गई। वह एक तरह से वाशिंगटन सहमति का भारत में विलम्ब से पहुँचना कहा जा सकता है। इसके अन्तर्गत उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण (LPG) की आर्थिक सुधार की प्रक्रियाओं का प्रारम्भ होना वर्ष 1990–91 के आर्थिक संकट के कारण स्वैच्छिक न होकर बाध्यकारी था। इसके (एल0पी0जी0) प्रथम चरण वर्ष 1993–94 से 2004–05 में बेरोजगारी की दर में वृद्धि 1.9 प्रतिशत से 2.3 प्रतिशत होने से बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या 7.4 मिलियन से बढ़कर 11 मिलियन हो गई। वर्ष 2005 से 2009 के मध्य बेरोजगारी की दर में न्यूनतम कमी 0.3 प्रतिशत की हुई, जबकि वर्ष 2011–12 में पुनः बढ़कर 2.2 प्रतिशत हो गई। भारतीय आर्थिक इतिहास में स्पष्टतया वर्ष 2005 से 2012 के मध्य उच्च संवृद्धि दर का चरण रहा। इस चरण में रोज़गार में होने वाली न्यूनतम वृद्धि जी0डी0पी0 में वृद्धि के कारण नहीं बल्कि बेरोज़गारी में होने वाली न्यूनतम कमी के फलस्वरूप हुई।

5. भारत में रोज़गार में वृद्धि की प्रवृत्ति निराशाजनक रही। 1970 के दशक में रोज़गार की मिश्रित वार्षिक संवृद्धि दर 2 प्रतिशत से अधिक थी। वर्ष 1973 से 1978 के मध्य रोज़गार की सी0ए0जी0आर0 2.7 प्रतिशत और वर्ष 1978 से 1983 के मध्य 2. 1 प्रतिशत रही। वर्ष 1983 से 1988 के मध्य रोज़गार वृद्धि दर घटकर 1.8 प्रतिशत हो गई। इसके पश्चात् अगले पाँच वर्षों में रोज़गार वृद्धि दर 2.3 प्रतिशत रही। वर्ष 1991 में शुरू हुए आर्थिक सुधारों के परिणामस्वरूप पुनः रोज़गार के स्तर में कमी आयी, लेकिन वर्ष 2000 से 2005 की अवधि में केवल 60 मिलियन अतिरिक्त रोज़गार सृजन से रोज़गार स्तर में थोड़ा सुधार हुआ।

अतः वर्ष 1993–94 से 2004–05 के मध्य रोज़गार की मिश्रित वार्षिक संवृद्धि दर 1.8 प्रतिशत के लगभग ही बनी रही। केवल 84.2 मिलियन अतिरिक्त रोज़गार सृजित हो पाया। रोज़गार संवृद्धि संबंधी महत्त्वपूर्ण चिन्ताजनक तथ्य वर्ष 2004–05 से 2009–10 के मध्य परिलक्षित हुए जब जी0डी0पी0 संवृद्धि दर उच्चतम और रोज़गार संवृद्धि दर घटकर 0.2 प्रतिशत हो गयी। इस समयावधि में केवल 5.7 मिलियन नये रोज़गार ही सृजित हुए। अगले दो वर्षों 2009–10 से 2011–12 के मध्य रोज़गार स्तर बढ़कर लगभग 1.0 प्रतिशत के निकट मुश्किल से पहुँच पाया।

Copyright © 2017, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

वर्ष 2004–05 से 2011–12 के मध्य सर्वाधिक वार्षिक संवृद्धि दर तथा प्रति व्यक्ति आय 6 प्रतिशत से अधिक होने के बावजूद वर्ष 2005 से 2012 के मध्य केवल 13 मिलियन अतिरिक्त नये रोज़गार सृजित हो पाये थे। इसके अतिरिक्त रोज़गार–लोच में होने वाली उत्तरोत्तर गिरावट, अर्थात् वर्ष 2000 से 2005 के मध्य 0.3 प्रतिशत से भी कम होकर वर्ष 2005 से 2012 के मध्य 0.05 प्रतिशत, का होना रोज़गार सृजन हेतु नियोजन प्रक्रिया की निराशाजनक उपलब्धि थी।

सैद्धान्तिक रूप से, श्रम शक्ति आधिक्य अर्थव्यवस्था में जी0डी0पी0 में होने वाली वृद्धि में त्वरण सुधारात्मक बाजार व्यवस्था द्वारा रोज़गार की वृद्धि दर को बढ़ाता है। अतः बाज़ार अर्थव्यवस्था में अधिकतम बाजार–निष्कपटता (उदारीकरण) द्वारा श्रम शक्ति आधिक्य अर्थव्यवस्था को उत्पाद विशिष्टीकरण और वस्तुओं के निर्यात की ओर प्रेरित करना चाहिए। जिससे उत्पाद–विशिष्टीकरण कर निर्यात सन्दर्भ में आधिक्य श्रम शक्ति का कार्यबल के रूप में तीव्र उपयोग हो सके। वैश्विक स्तर पर उदारीकरण द्वारा रोज़गार सृजन सम्बन्धी प्राप्त परिणाम संतोषजनक नहीं हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था भी इसका अपवाद नहीं है। इसकी पुष्टि रोज़गारहीन आर्थिक संवृद्धि द्वारा स्वतः होती है।

vkfFkd fu;ktu dh iklfxdrk gr l>ko–

1. वर्ष 1993 में विश्व बैंक का **'द ईस्ट एशियन मिरैकल'** नामक प्रकाशित अध्ययन और वर्ष 1999 में विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट में आर्थिक व्यवस्थाओं (Economic Systems) पर लगभग अन्तिम विचार प्रस्तुत करते हुए मिश्रित अर्थव्यवस्था को एक बेहतर विकल्प बताया गया। इस बात पर बल दिया कि अर्थव्यवस्था की सामाजिक–आर्थिक स्थिति के अनुसार आर्थिक निर्णय लिए जायें।
2. नियोजन द्वारा ही कृषि व उससे सम्बन्धित क्षेत्रों में प्राथमिकता के आधार पर नये सिरे से विकेन्द्रीकरण विकास प्रक्रिया का क्रियान्वयन किया जाये जिससे निम्न उत्पादकता और प्रच्छन्न बेरोज़गारी को दूर कर कृषि उद्योग की मन्दता को समाप्त किया जा सके।
3. भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में 51 प्रतिशत परिवारों की कुल सम्पत्ति में हिस्सा केवल 10 प्रतिशत है और शहरी क्षेत्रों में 50.7 प्रतिशत परिवारों के पास कुल परिसम्पत्ति का केवल 5.3 प्रतिशत है। परिसम्पत्तियों के इस दोषपूर्ण वितरण को नियोजन द्वारा ही

कम करके निम्नस्तरीय मानव पूँजी को उच्च स्तरीय मानव पूँजी में बदला जा सकता है। अमेरिकी अर्थशास्त्री जेम्स0एस0 ड्यूजनबेरी ने अपने अनुभवजन्य तथ्य के आधार पर सिद्ध किया है कि आर्थिक असमानता जैसे–जैसे कम होती है, वैसे–वैसे पूँजी संचय (निवेश) बढ़ता है।

4. नियोजन एक लगातार चलने वाली एवम् सतत् बढ़ने वाली प्रक्रिया है। इसे चुनाव परिणामों की अनियमितताओं के भरोसे न छोड़ा जाये। आवश्यक है कि एक दृढ़ राष्ट्रीय चरित्र, हो जो बिना किसी मानसिक बाधा परिग्रह के सभी राजनैतिक दलों के मध्य ''योजना की आवश्यकता की एक सार्वभौमिक'' सहमति बना सके। नियोजन और सामाजिक एवं सांस्कृतिक अभिवृत्तियों में एकरूपता होनी चाहिए जिससे आर्थिक विकास हेतु सकारात्मक जन–सहभागिता प्राप्त हो सके।

lUnHkZ lwph–

डॉ0 थॉमस बलोग : इकनोमिक बैलेंस बिट्वीन दी ईस्ट एण्ड द वेस्ट, कॉमर्स,: एनुअल 1958।

उपाध्याय, निर्मलाय : ''महात्मा गाँधी की स्वराज विषयक धारणा'' लोकतंत्र समीक्षा, जुलाई–दिसम्बर 1982, अंक 3–4, पृष्ठ 311 से 314।

टी0एस0 पपोला : ग्रोथ एण्ड स्ट्रक्चर ऑव एम्प्लॉयमेंट इन इण्डिया, मार्च 2012।

चौधरी, सुभानिल (2011) ''एम्प्लॉयमेंट इन इण्डिया, व्हॉट इज़ द लेटेस्ट डाटा शो?'' इकनोमिक एण्ड पॉलिटिकल वीकली, अगस्त 6।

मिश्रा, संगीता एण्ड सुरेश के0 अनूप : एस्टिमेटिंग एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी ऑव ग्रोथ फार दी इण्डियन इकॉनमी, जून 2014।

अग्रवाल, आराधना (2014) : न्यू इनसाइट्स इनटू द रिलेशनशिप बिट्वीन एम्प्लॉयमेंट एण्ड इकनोमिक ग्रोथ इन इण्डिया।

आर्थिक समीक्षा 2011–12।

आर्थिक समीक्षा 2013–14।

आर्थिक समीक्षा 2014–15।

एन0एस0एस0ओ0 रिपोर्ट संख्या 484।

एन0एस0एस0ओ0 रिपोर्ट संख्या 554।

नेशनल एकाउण्ट्स स्टैटिस्टिक्स 2014 विवरण।

Copyright © 2017, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies